International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 5, Issue 2, February 2018
Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

सतत विकास में नवीन शिक्षा पध्दति का योगदान

श्रीमति एम. सुजाता राव (सहायक प्राध्यापक)
सांदीपनी एकेडमी, अछोटी, (मुरमुंदा), दुर्ग (छ.ग.)

सारांश

सतत विकास के लिए नवीन शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो ना केवल राष्ट्रीय विकास में बल्कि सतत विकास में भी योगदान देता है। यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक या पर्यावरण विकास की कुंजी है।सतत विकास को प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक ज्ञान और कौशल के विकास को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक कल्याण सामाजिक समानता लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुत सी चीजों को प्रोत्साहित करती है। सतत विकास के लिए शिक्षा लोगों और नागरिकों को यह जानने में सक्षम बनाती है। कि पृथ्वी के संसाधन को कैसे सुरक्षित किया जाए जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। कि एसडी का उद्देश्य एसडी के आर्थिक सामाजिक आयामों के लिए एक संतुलित एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग कर वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सामर्थ बनाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व और रचनात्मकता को विकसित करने की एक प्रक्रिया है ताकि वे स्वस्थ समाज और प्रगति को बढ़ावा देने में सहायता कर सकें। शिक्षा वास्तव में एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति क्षमताओं सामाजिक वातावरण, आर्थिक विकास ,आसपास के नैतिक और विशेषकर सभी अनुकूलन क्षमताओं को प्रभावित करता है।शिक्षा से अपेक्षा की जाती है, कि वह ज्ञान के अनुसरण के लिए सिद्धांतों विधियों दिशानिर्देशों कर विकसित करें। ताकि समाज को लाभ पहुंचाया जा सके । विकास की समस्या के समाधान के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। लोगों छात्रों के शारीरिक और सामाजिक वातावरण के बगैर ने समाज और दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होती है। सतत विकास जून 1992 में ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्य केंद्र था विश्व स्तर पर सतत विकास की उपलब्धि जनसंख्या वृद्धि में प्रति व्यक्ति खपत के बढ़ते स्तर के कारण विश्व समुदाय के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सिद्ध होने की संभावना है। जैसे कि पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने निरीक्षण किया, कि जलवायु परिवर्तन ओजोन अधिकरण और प्रजाति हानि जैसे वैश्विक कठिनाइयों के अतिरिक्त दबाव के बीच सतत विकास को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सतत विकास पर्यावरण और विकास पर वित्त आयोग की रिपोर्ट जिसका शिक्षक रखा गया था हमारा सामुदायिक भविष्य को जिम्मेदार ठहराया गया को परिभाषित करती है सतत विकास आर्थिक विकास परिस्थिति सत्ता के बीच संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करता है, दोनों आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों को जीवित रखने के लिए एक निश्चित न्यूनतम

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

प्रारंभ को आवश्यकता होती है, संक्षेप में सतत विकास परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें संसाधन का उपयोग निवेश की दिशा तकनीकी विकास उन्मुखीकरण संस्थागत परिवर्तन सभी सामजस्य में है, और मानव की जरूरत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान और भविष्य की क्षमता दोनों को बढाते हैं।

प्रस्तावना –

सतत विकास के लिये शिक्षा एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जो सभी रूपों में चलने वाले शैक्षिक क्रियाकलापों को अंतर्निहित करती है। इसके अंतर्गत औपचारिक सहज तथा गैर औपचारिक सभी प्रकार की शैक्षिक प्रणालियां आ जाती हैं। सतत विकास के लिय नवीन शिक्षा, मूल्य शिक्षा को जीवन और जीवन को शिक्षा समझने वाली अवधारणा है। व्यापक अर्थ में सतत शिक्षा यह जीवन शिक्षा जन्म से मृत्यु तक अविरल चलने वाली प्रक्रिया है। सतत शिक्षा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं। सतत शिक्षा व्यक्तियों को इस योग्य बनाती है कि वह अपने उपयुक्त कौशलों योग्यताओं एवं व्यक्तियों का विकास कर सकें। सतत शिक्षा एक नवीन क्षेत्र है और यह सामाजिक अणु को विखंडित करने के लिए शक्तिशाली अस्त्र के समान है जो हमारे समाज परिवर्तन की ओर उन्मुख है और सतत शिक्षा ही उचित दिशा प्रदान कर सकती है।

सतत शिक्षा निरंतर चलने वाला एक ऐसा प्रयास जो जीवन पथ पर चलने वाले व्यक्ति की अपनी व्यावहारिक समस्याओं के लिए आजीवन अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह शैक्षिक प्रयासों को व्यक्ति जीवन अनुभवों को प्रकाश में उसके जीवन से संदर्भित करने का आवेदन प्रयास है। आधुनिक भारतीय समाज परिवर्तन भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप भारतीय समाज अर्थ परिभाषा आधार भारतीय समाज का बालक पर प्रभाव धर्मनिरपेक्षता अर्थ विशेषताएं आर्थिक विकास संस्कृति अर्थ महत्व सांस्कृतिक विरासत मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रजातंत्र परिभाषा व रूप प्रजातंत्र के गुण व दोष लोकतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य सतत शिक्षा भारत में नव सामाजिक व्यवस्था जनतंत्र अर्थ जनतंत्र और शिक्षा

स्त्री शिक्षा विकलांग शिक्षा भारत में स्त्री शिक्षा का विकास शब्द 'सतत विकास' का सबसे पहली बार प्रयोग 'वर्ड कन्सर्वेशन स्ट्रेटजी' द्वारा किया गया जिसे 'प्रकृति और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ' ने 1980 में प्रस्तुत किया। ब्रण्डटलैण्ड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना पूरा करना।

सतत विकास के लिये शिक्षा–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सदस्य शिक्षा मानव विकास संसाधन की रणनीति का एक आवश्यक पक्ष है इसका लक्ष्य सीखने के योग्य समाज की रचना करना है। यह नवसाक्षर एवं अधूरी पढ़ाई छोड़ने वाले के लिए उत्तर साक्षरता की व्यवस्था करती है, जिससे वह साक्षरता युक्त कौशल को धारण करने प्रारंभिक साक्षरता के बाद सीखने के क्रम को जारी रखने तथा अपने जीवन स्तर में गुणात्मक विकास के लिए सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक बनाने में सक्षम हो सकें।

सतत शिक्षा के उद्देश्य–

1. लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार
2. साक्षरता का प्रसार
3. वयक्तिक उत्थान
4. महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए

सतत शिक्षा की विशेषताएं

उपयुक्त विवेचन के आधार पर सतत शिक्षा के निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। सतत शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए होती हैं। यह विशिष्ट परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुआयामी कथा बहुउद्देशीय होती हैं। यह सभो के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए मुक्त या खुली होती हैं। यह अनुकूलन को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। क्राफ्ट लेवा दवे ने सतत शिक्षा की विशेषताओं को निम्नलिखित आयामों के रूप में प्रस्तुत किया है।

1. सतत शिक्षा समग्र शिक्षा है इसमें संपूर्णता पर बल दिया जाता है।
2. यह समन्वित शिक्षा है।
3. यह लचीली शिक्षा है।
4. यह खुले पन पर बल देती है।
5. यह जनतांत्रिक शिक्षा है।

सतत शिक्षा की विधियां तथा माध्यम भारत में सतत शिक्षा मुख्यता चार प्रकार की शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित है।

1. साक्षरता सहित न्यूनतम प्रारंभिक शिक्षा
2. साक्षरता पुण्य शिक्षा
3. सांस्कृतिक मूल्योंमुख शिक्षा
4. पर्यावरणीय शिक्षा

सतत शिक्षा के उद्देश्य–

सतत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत साक्षरता कौशल को बनाए रखना एवं उसका विकास करना तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों में समाज के सभी सदस्यों की सहभागिता बढ़ाना। साथ ही साथ व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की व्यवस्था करना और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना।

सतत शिक्षा मानव संसाधन के विकास के उपाय का और ऐसे समाज के निर्माण के दे का अनुवाद पहलू है जो निरंतर ज्ञानार्जन करता रहता है सतत शिक्षा में 9 अक्षरों तथा पढ़ाई पूरी किए बगैर ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की उत्तर साक्षरता भी शामिल है जिसका उद्देश्य है कि शिक्षार्थी अपनी साक्षरता बनाए रखें प्रारंभिक शिक्षा के आगे अपनी शिक्षा जारी रखें तथा इस शिक्षा से अपने जीवन को अधिक अच्छा बनाएं।

सतत शिक्षा की सार्थकता व उद्देश्य निम्नवत है –

1. लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार।
2. साक्षरता का प्रसार
3. वयक्तिक उत्थान ।
4. महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए।

1. लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार–

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की रक्षा व प्रसार इसका मुख्य ध्येय है। सभी के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता महिलाओं अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए शिक्षा प्रोड शिक्षा का प्रसार आदि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की सुरक्षा व प्रसार देश के सुशिक्षित नागरिक के माध्यम से ही संभव है। यह शिक्षा नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी देती है और कुशल मानवीय संसाधन के विकास में योगदान करती है।

2. साक्षरता का प्रसार –

बहुल जनसंख्या को देखते हुए भारत में साक्षरता का प्रतिशत अभी भी कम है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए साक्षरता अभिशाप हैं देश में साक्षरता का प्रसार करने में सतत शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है साक्षर पौधों के लिए भी उत्तर साक्षरता आवश्यकता होती है अनवरत शिक्षा के द्वारा उत्तर साक्षरता के कार्यक्रम सुगमता से चलाए जाते हैं।

3. वयक्तिक उत्थान –

किसी भी देश के लिए यह आवश्यक होता है कि उस देश के नागरिकों को व्यक्तित्व उत्थान होता रहे इससे उस राष्ट्र की उन्नति और विकास निर्भर रहता है सामान्य शिक्षा प्राप्त करके प्राया लोग जीवन यापन करने लगते हैं परंतु यदि उन्हें अवसर मिले तो वह आगे भी ज्ञानार्जन कर अपने ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व उत्थान किया जा सकता है और उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास किया जा सकता है।

4. महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए –

भारत में महिला साक्षरता आज भी पुरुषों की तुलना में कम है जिससे उनके जीवन स्तर वह सोच का दायरा अत्यंत सीमित रहता है महिलाओं की स्थिति बेहतर करने की दिशा में अनवरत शिक्षा का एक कारगर उपाय है अनवर शिक्षा के द्वारा महिलाएं अपने और अधिकारों को समझ सकेंगे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से मुक्त होने का प्रयास करें कि वह अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति सजग एवं जागरूक हो सकेंगे।

सतत विकास के लिये नीतियां:–

प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण विश्वास है कि कृषि, उद्योग, शहरीकरण तथा संरचना क्षेत्रों में होने वाला सर्वागीण विकास तथा जनसंख्या की वृद्धि पर्यावरणीय अवनति की ओर ले जाते हैं। अन्य शब्दों में पर्यावरणीय अवनति मानवीय स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, आर्थिक उत्पादकता को कम करती है तथा सुख–सुविधाओं की हानि की ओर ले जाती है।

पर्यावरणीय अवनति के हानि कारक प्रभावों को कम करने के लिए आर्थिक एवं पर्यावरणीय नीतियों का न्यायसंगत चयन और पर्यावरणीय निवेश समय की आवश्यकता है।

1. निर्धनता को कम करना –

सर्व प्रमुख नीति निर्धनता को दूर करना है इसलिये ऐसी परियोजनाएं आरम्भ की जानी चाहिये जो निर्धन वर्ग को राजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करें। सरकार को चाहिये कि स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शिक्षा सेवाओं का विस्तार करें, जिससे जनसंख्या को कम करने मे सहायता मिलेगी।

नागरिक सुविधाओं जैसे पीने के जल की पूर्ति, सफाई की सुविधाएं, गन्दी बस्तियों के स्थान पर अच्छे निवास स्थान आदि देश में पर्यावरण के सुधार में बहुत सहायक होंगे।

2. वित्तीय सहायताओं की समाप्ति –

किसी वित्तीय लागतों के बिना पर्यावरणीय अवनति को कम करने के लिये सरकार को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को संसाधनों के प्रयोग के लिये दी गई रियायतों को समाप्त किया जाना चाहिए ।

वास्तव में, इन रियायतों के कारण, बिजली, उर्वरकों, कीटनाशकों, डीजल, पैट्रोल, गैस, सिंचाई के जल आदि का दुरुपयोग होता है । बदले में य सब पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इन रियायतों की समाप्ति अथवा इनको कम करने से देश को सब ओर से लाभ प्राप्त होगा।

3. बाजार आधारित अभिगम –

पर्यावरण के बचाव के लिये बाजार आधारित अभिगमों को अपनाने की अत्याधिक आवश्यकता है। वे उपभोक्ताओं और उद्योगों को पर्यावरण पर प्राकृतिक साधनों के प्रयोग की लागत के सम्बन्ध में बताते हैं। बाजार आधारित उपकरण (MBIS) सर्वोत्तम नीति है।

ये दो प्रकार की हैः–

(i) मात्रा आधारित और कीमत आधारित वे पर्यावरणीय करों के रूप में होते हैं जिनमें सम्मिलित हैं– प्रदूषण खर्चे (निस्सरण करध्प्रदूषण कर) विपणन योग्य आज्ञा पत्र, जमाकर्त्ता कोष प्रणाली, आगत करध्उत्पाद खर्चे, विविध प्रकार के कर दरें और उपयोगकर्त्ता के प्रशासनिक खर्चे,

(ii) वायु और जल साधनों के लिये प्रदूषण कम करने से सम्बन्धित साज–सामान के लिये आर्थिक सहायता।

4. सम्पत्ति अधिकारों का वर्गीकरण –

प्रसारसाधनों के अत्याधिक उपयोग पर सम्पत्ति अधिकारों का अभाव पर्यावरण को अवनति की ओर ले जाता है। इस कारण सांझी अथवा सार्वजनिक भूमि पर अधिक चराई, वनों की कटाई तथा खनिजों तथा मत्स्य क्षेत्रो का अत्याधिक प्रयोग हो जाता है।

निजी स्वामियों के स्वामित्व के अधिकार तथा आवधिक अधिकार स्पष्ट कर देने से पयावरणीय समस्याएं दूर हो जायेंगी। अतः सरकारी रिकार्ड में स्वामित्व के अधिकार पूर्णतया स्पष्ट होने चाहिये।

5. आर्थिक प्रोत्साहन–

कीमत, मात्रा और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित आर्थिक प्रोत्साहन पर्याप्त सहायता कर सकते हैं। प्रोत्साहन प्रायः साधनों के प्रयोगकर्त्ताओं को वायु, जल और भूमि के प्रयोग में प्रदूषकों की मात्रा के लिये विविधतापूर्वक शुल्कों के रूप में दिये जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित निस्सरण मानकों से कम प्रदूषण उत्पन्न करने पर उन्हें के दी जाती हैं।

6 नियामक नीतियां –

पर्यावरणीय अवनति को कम करने के लिये प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शस्त्र नियामक नीतियां हैं । नियन्त्रक को कीमत, प्रदूषण की मात्रा कीमत अथवा साधन प्रयोग अथवा तकनीकों के सम्बन्ध में निर्णय करने होते हैं। नियामक अधिकारी निर्णय यह लेता है कि क्या नीतियों को प्रत्यक्ष रूप में पर्यावरणीय समस्याओं को लक्षित करना चाहिये अथवा परोक्ष रूप में।

वह तकनीकी मानकों का निर्धारण करता है और वायु, जल, भूमिप्रदूषकों पर नियम और खर्चे निर्धारित करता है। नियामक प्राधिकरण को पर्यावरणीय मानक लागू करने में सार्वजनिक एवं निजी प्रदूषणकर्त्ताओं अथवा साधन प्रयोगकर्त्ताओं के प्रति भेदभाव रहित होना चाहिये।

7. व्यापार नीति –

पर्यावरण के सम्बन्ध में व्यापार नीति के दो उलझाव हैंः–

(i) घरेलू नीति सुधारो के सम्बन्ध में,

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से सम्बन्धित।

घरेलू व्यापार नीति कम प्रदूषण वाले उद्योगों को शहरों से दूर स्थापित करने पर बल देती है तथा प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये साफ–सुथरी तकनीकें अपना कर पर्यावरण हितैषी प्रक्रियाओं पर बल देती है।

8. सार्वजनिक जागरूकता –

सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता पर्यावरणीय स्थितियों को सुधारने में बहुत सहायक हैं। पर्यावरण प्रबन्ध और पर्यावरण जागरूकता से सम्बन्धित औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर्यावरण की अवनति को नियन्त्रित करने में और पर्यावरण को साफ–सुथरा रखने में बहुत सहायता करते हैं।

इसलिये लोगो का सहयोग लागत रहित एवं उपयोगी वन लगाने, वन्य जीवन के संरक्षण, उद्यानों की व्यवस्था, सफाई तथा जल विकास प्रणाली और बाढ़ नियन्त्रण आदि में सहायता उपलब्ध करता है।

9. सार्वभौम पर्यावरण प्रयत्नों के लिये –

आधुनिक काल में यह महसूस किया जाता है कि सार्वभौम पर्यावरण प्रयत्नों में सहभागिता पर्यावरण की अधोगति उत्पन्न हानियों का न्यूनतम बनाने में सहायता करती है । इसलिये पर्यावरण के संरक्षण पर समझौते करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये।

सतत विकास के लिए नवीन शिक्षा में निम्नलिखित चुनौतियों को शामिल किया गया है

1. सतत विकास से संबंधित मौलिक शिक्षा का बढ़ावा और सुधार।
2. मौजूदा शैक्षिक को सभी स्तरों प्राथमिक मौलिक, माध्यमिक कामा सतत विकास को संबोधित करने के लिए उच्च शिक्षा का पुनः अनु स्थापना करना।
3. जन जागरूकता विकसित करना और सत्यता को समझाना।
4. सतत विकास की दुनिया में प्रशिक्षण विधियों को सिखाना और विकसित करना।

निष्कर्षः–

विश्व के देशों के सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को संयुक्त राष्ट्र महासभा में महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त है 2015 में प्रस्ताव शिक्षा तीव्र आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति प्राप्त करने और स्वतंत्र सामाजिक न्याय और समान अवसर के मूल्यों पर स्थापित सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा के लिए सबसे महत्वपूर्ण के कल कारक है । शिक्षा के कार्यक्रम लोगों की ऊर्जा का उपयोग करने और देश के प्रत्येक भाग के प्राकृतिक और मानव संसाधन को विकसित करने के लिए आम नागरिकों के बंधन को बनाए रखने के प्रयास के आधार पर निहित है एक शब्द में शिक्षा को विकास की कुंजी के रूप में माना जाता है और सामाजिक और आर्थिक न्याय मौलिक अधिकार पर अपेक्षित है जो कल्याणकारी राज्य से जुड़ाव स्तंभ है ।विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित विश्व में यह शिक्षा है, जो लोगों की समृद्धि कल्याण सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करता है। सतत विकास के लिए शिक्षा की प्राथमिक चिंता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है कहा गया है, कि एक साथ देखे गए थे हमारे सारे भविष्य की एक साहसिक और सुंदर दृष्टि प्रदान करता है ।एक ऐसा भविष्य जिसमें लाखों लोग अब प्रत्येक दिन भूखे नहीं सोएंगे जहां गरीब आप दस लोगों में से एक को नहीं बताएंगे और यहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसर सभी के लिए उपलब्ध होगी ।विकास के साथ–साथ विकासशील देशों के कार्यक्रम की विविधता वर्तमान में सतत विकास के लिए शिक्षा पर किसी भी कार्य योजना के लिए एक विधिवत वर्तमान में सतत विकास जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग में उपयोगी अवसर प्रदान करता है। ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी जनसंख्या नियंत्रण स्वच्छता कार्यक्रम आदि ,के लिए सात अभियान चलाने के लिए कुछ निरंतर प्रयास है। जलवायु परिवर्तन अभियान सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा अभ्यास में मॉडल के रूप में कार्य करता है। नवाचार और ईएसडी की नई परियोजना संबंधित शिक्षा क्षेत्रों को वरिष्ठ नागरिकों संघों धार्मिक संस्थाओं आदि जैसे सभ्य सामाजिक समूह को शामिल करने लोकप्रिय बनाने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस तरह सतत विकास वास्तव में देश की समृद्धि और लोगों की खुशी में योगदान देता है। यह लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को भी सुनिश्चित करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1 शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य

UNECE. (2016).The years of the UNECE strategy for education for education for sustainable development .Retrievend from

World Bank. (1992). World development report development and environment. New York: Oxford University presses